Date: 06.02.2025

To,

The Manager
Department of Corporate Service
BSE Limited
P.J. Towers Dalal Street, Mumbai - 400001

SCRIP CODE: 531499 (SYBLY INDUSTRIES LTD) EQ - ISIN - INE080D01042.

Subject: Submission of Extract of Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the quarter ended on December 31st, 2024.

Dear Sir/Madam,

With reference to the above captioned subject, please find herewith enclosed copies of Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the quarter ended on December 31st, 2024. Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Financial Results was published in one English Newspaper **"English Daily Open Search"** and in one Hindi Newspaper **"Hindi Daily Open Search"** in the language of the region where the registered office situated. The web link for the direct access to the abovementioned newspaper advertisement is https://www.opensearch.co.in/33011/ and https://www.opensearch.co.in/33009/.You are requested to take the above on your records and acknowledge the same.

You are requested to take the above on your records and acknowledge the same.

Thanking You.

For and on behalf of Board of Directors
SYBLY INDUSTRIES LIMITED

Chirag

Digitally signed by Chirag
DN: cn=Chirag, c=IN, st=Haryana, o=Personal, title=9532, serialNumber=1ffbd9b0bf5c4fcb54c375b72f310421578fe55dd65d06496e5cb682ec9187c9
Date: 2025.02.06 13:21:59 +05'30'

CHIRAG
DIRECTOR
DIN: 10728185

Date: 06.02.2025
Place: New Delhi

Encl: As above

गोरखपुर-झूसी के बीच 7 फेरा में चलाई महाकुंभ स्पेशल

गोरखपुर से झूसी के बीच सात फेरा में आरक्षित महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई, रेलवे प्रशासन ने महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर समय सारिणी, रूट और ठहराव भी जारी कर दिया

गोरखपुर (एजेंसी)

वसंत पंचमी के बाद माघ पूर्णिमा स्नान तक महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। बुधवार से गोरखपुर से झूसी के बीच सात फेरा में आरक्षित महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई, रेलवे प्रशासन ने महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर समय सारिणी, रूट और ठहराव भी जारी कर दिया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए इंटरसिटी सहित वाराणसी-प्रयागराज रूट पर निरस्त ट्रेनों का संचालन भी बुधवार से बहाल कर दिया है।

यह ट्रेनें पूर्व निर्धारित, समय, रूट और ठहराव के आधार पर चलाई जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 05004/05003 नंबर की गोरखपुर-झूसी-गोरखपुर आरक्षित महाकुंभ स्पेशल चलाई जाएगी। यह स्पेशल ट्रेन गोरखपुर से 05, 06, 07, 09, 10, 11 एवं 12 फरवरी को तथा झूसी से 06, 07, 08, 10, 11, 12 एवं 13 फरवरी को चलाई जाएगी। इस ट्रेन में शयनयान श्रेणी के 07, साधारण द्वितीय श्रेणी के 05, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का 01 तथा वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनामी के 07 सहित कुल 22 कोच लगाए।

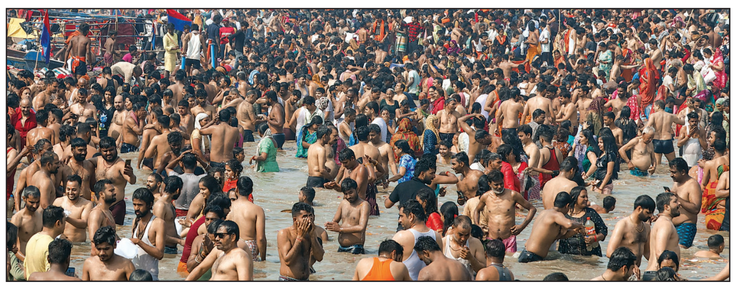

- 05004 गोरखपुर-झूसी महाकुंभ मेला स्पेशल गोरखपुर से रात 09:30 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन चौरी चौरा, देवरिया सदर, भटनी, मऊ और बनारस होते हुए दूसरे दिन सुबह 06:00 बजे झूसी पहुंचेगी।
- 05003 झूसी-गोरखपुर महाकुंभ स्पेशल झूसी से सुबह 07.45 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन हंडियाखास, ज्ञानपुर रोड, माधो सिंह, बनारस, मऊ, भटनी और देवरिया होते हुए शाम को 04:25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

पूर्व निर्धारित समय, रूट व ठहराव पर चलने वाली ट्रेनें

- 15130 वाराणसी सिटी-गोरखपुर कैंट एक्सप्रेस।
- 15129 गोरखपुर कैंट-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस।
- 15104 बनारस- गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस।
- 15103 गोरखपुर- बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस।
- 14232 बस्ती- प्रयागराज संगम एक्सप्रेस।

गोरखपुर से प्रयागराज के बीच चल रहीं रोडवेज की 390 महाकुंभ स्पेशल बसें

वसंत पंचमी स्नान के बाद गोरखपुर परिक्षेत्र से प्रयागराज के बीच दूसरे डिपो की चल रही रोडवेज की 1910 महाकुंभ स्पेशल बसें वापस होने लगी हैं। हालांकि, गोरखपुर परिक्षेत्र की 390 महाकुंभ स्पेशल बसें माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि स्नान पर्व तक चलती रहेंगी। प्रयागराज और महाकुंभ मेला क्षेत्र में गोरखपुर की 50 बसें शटल सेवा के रूप में चल रही हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गोरखपुर परिक्षेत्र के स्टापेज ही नहीं प्रयागराज के सीमावर्ती क्षेत्रों और झूसी में सैकड़ों बसें खड़ी हैं। दरअसल, वसंत पंचमी तक गोरखपुर परिक्षेत्र के 38 प्वाइंटों से होकर पौष पूर्णिमा से 2300 महाकुंभ स्पेशल बसें चलाई गई हैं। हालांकि, मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर करीब एक हजार बसें प्रयागराज में ही फंस गईं। बसों का संचालन बाधित होने से श्रद्धालु भी महाकुंभ से बाहर नहीं निकल पाए। श्रद्धालुओं को वापस लाने के लिए परिवहन निगम ने गोरखपुर और राप्तीनगर डिपो सहित गोरखपुर परिक्षेत्र से 180 अनुबंधित बसें प्रयागराज भेजी थीं। इसके पहले 26 से 28 जनवरी तक तीन दिन में गोरखपुर परिक्षेत्र से श्रद्धालुओं को प्रयागराज भेजने के लिए गोरखपुर और राप्तीनगर डिपो की लगभग सात सौ बसें महाकुंभ के लिए भेजी गईं। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर परिवहन निगम प्रबंधन ने सोनौली, महराजगंज, बस्ती, लखनऊ और दिल्ली जाने वाली बसों को भी महाकुंभ के लिए रवाना कर दिया। गोरखपुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चन्द्र कहते हैं कि पूरा प्रयास किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं और यात्रियों को कोई परेशानी न हो।

नोएडा के नामी स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा टीमों ने की जांच, सब सामान्य

नोएडा (एजेंसी)

नोएडा के नामी स्कूलों को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी का मेल मिला है। इनमें स्टेप बाई स्टेप स्कूल, द हेरिटेज स्कूल, ज्ञानश्री स्कूल और मयूर स्कूल को एक स्पैम ईमेल द्वारा बम की धमकी प्राप्त हुई। इस सूचना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस, बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वायड और बीडीएस टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया, जिन्होंने स्कूलों की गहन जांच की। पुलिस ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं रही, क्योंकि जांच के बाद सभी स्कूलों में स्थिति सामान्य पाई गई। कई स्कूलों में कक्षाएं फिर से शुरू हो चुकी हैं। इस मामले में साइबर टीम द्वारा भेजे गए ईमेल की विवेचना की जा रही है, ताकि इस धमकी के पीछे के असल कारणों का पता चल सके। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और संयम बनाए रखें। गौरतलब है कि बीते साल दिल्ली, नोएडा और एनसीआर के कई स्कूलों में लगातार धमकी भरे मेल मिलने का सिलसिला जारी रहा था, जिसके बाद स्कूल तक पहुंचे बच्चों को वापस घर के लिए रवाना कर दिया गया था और इसकी जानकारी पुलिस

टीम को दी गई थी। फिलहाल एहतियात के तौर पर सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है और बम स्क्वॉड की टीम के साथ छानबीन की जाती है। फिलहाल यह धमकी भरा मेल भेजने वाले अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। साइबर सेल की टीम लगातार ऐसे मेल भेजने वालों को ट्रेस करने की कोशिश में जुटी हुई है। यह सिलसिला लगातार जारी है और अगर बात करें तो बीते साल ही दो महीने के अंदर दिल्ली के ही कई स्कूलों में लगभग 11 बार बम की धमकियां मिल चुकी हैं।

गौरव यादव के स्थायी डीजीपी बनने का रास्ता साफ, पंजाब सरकार केंद्र को भेजेगी पैनल

चंडीगढ़ (एजेंसी)

आईपीएस अधिकारी गौरव यादव का स्थायी तौर पर डीजीपी बनने का रास्ता साफ हो गया है। गौरव यादव से सभी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सेवानिवृत्त

हो चुके हैं। राज्य में आप सरकार बनने के बाद गौरव यादव कार्यकारी डीजीपी के तौर पर काम कर रहे हैं।

1987 बैच के आईपीएस अधिकारी और पूर्व डीजीपी वीके भावरा के छुट्टी पर जाने के बाद गौरव यादव को 4 जुलाई 2022 को डीजीपी का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया था। इसके बाद स्थायी डीजीपी लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से कभी भी पैनल नहीं भेजा गया। करीब ढ़ाई साल बाद अब राज्य सरकार की ओर से स्थायी डीजीपी लगाने के लिए केंद्र को पैनल भेजा जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से केंद्र को जो पैनल भेजा जा रहा है उसमें डीजीपी यादव सबसे वरिष्ठ हैं। इनसे पहले जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे या तो वह सेवानिवृत हो गए हैं या फिर केंद्रीय डेपुटेशन पर हैं। 1987 बैच के आइपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता एनआईए प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 1987 बैच के आईपीएस वीके भावरा पंजाब पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन के एमडी के पद से पिछले साल मई में सेवानिवृत्त हुए थे। इसी तरह 1988 के बैच के आईपीएस अधिकारी प्रबोध कुमार बीते सप्ताह ही सेवानिवृत्त हुए हैं। 1989 बैच के आइपीएस अधिकारी पराग जैन भी केंद्रीय डेपुटेशन पर है। इसी बैच के आइपीएस अधिकारी संजीव कालडा भी इस माह 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

गौरव यादव 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इनके बैच के आईपीएस हरप्रीत सिंह सिद्धू इस समय केंद्रीय डेपुटेशन पर है। इसी बैच के आईपीएस शरद सत्या चौहान भी इस समय पंजाब पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन, आईपीएस कुलदीप सिंह इस समय स्पेशल डीजीपी एसटीएफ हैं। गौरव यादव करीब तीन साल से डीजीपी के तौर पर काम कर रहे है, इसलिए उनका स्थायी डीजीपी लगना लगभग तय है। हालांकि उनको डीजीपी लगाने के विरोध में पूर्व आईपीएस अधिकारी वीके भावरा ने कैट का रुख किया था, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली थी। राज्य में इस समय करीब 16 डीजीपी हैं।

अमृतसर में पुलिस और आतंकी के गुर्गों के बीच मुठभेड़, चकमा देकर भागने की थी प्लानिंग

अमृतसर (एजेंसी)

कनाडा बैठे गैंगस्टर से आतंकी बने लखबीर सिंह उर्फ हरिके के इशारे पर पंजाब से रंगदारियां वसूल करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को छेहरटा थाने की पुलिस ने मंगलवार की रात काबू किया है। आरोपितों में से जगरूप सिंह उर्फ चरना ने पुलिस को गच्चा देकर उल्टी का बहाना किया और पुलिस वाहन से नीचे उतार दिया गया।

इस बीच आरोपित ने मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश की। चरना को काबू करने के लिए पुलिस ने उसकी टांग पर गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया। इंस्पेक्टर विनोद कुमार को सूचना मिली थी कि विदेश में बैठे कुख्यात आतंकी लखबीर सिंह उर्फ हरिके के इशारे पर तरनतारन के पट्टी निवासी जगरूप सिंह उर्फ चरणा, तलवंडी मेहर निवासी जुगराज सिंह उर्फ काजी और शमशेर सिंह उर्फ शेरा कारोबारियों को डरा धमका कर रंगादरी वसूल कर रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने छापामारी कर तीनों को काबू कर लिया। उनके कब्जे से 32 बोर का एक पिस्तौल, दो कारतूस बरामद किए गए। उक्त तीनों आरोपित इलाके मे रहने वाले एक कारोबारी की रेकी करने पहुंचे थे। इससे पहले आरोपित ने लखबीर सिंह हरिके को कारोबारी के घर, कारों और कार्य स्थल की फोटो खींच कर अपने मोबाइल के जरिए विदेश में भेजी थी। इसी आधार पर आरोपित लखबीर सिंह हरिके विदेश में बैठकर कारोबारी को उसकी फोटो भेज कर डरा धमका कर लाखों रुपये रंगदारी की मांग कर रहा था। पुलिस जब तीनों आरोपितों को काबू कर थाने ला रही थी तो गैंगस्टक चरणा ने पुलिस को बताया कि उसे पुलिस वाहन में घबराहट हो रही है। उसे उल्टी होने वाली है। इसके बाद पुलिस, ने उसे अपने वाहन से नीचे उतार दिया।

खेतों के ट्यूबवेल का ही पानी पियेंगे डल्लेवाल, खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता का एलान

संगरूर (एजेंसी)

खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरणव्रत मंगलवार को 71वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को हरियाणा राज्य के पचास गांवों से किसान अपने खेतों के ट्यूबवेल का पानी लेकर खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल को पिलाने पहुंचे।

इसके साथ ही ऐलान किया कि यही पानी जगजीत सिंह डल्लेवाल को पिलाया जाएगा, क्योंकि इन ट्यूबवेलों वाले खेतों की जमीन को बचाने की खातिर ही डल्लेवाल मरणव्रत कर रहे हैं। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि डल्लेवाल पिछले 71 दिन से अनशन पर हैं, जिन्होंने 71 दिन से कुछ नहीं खाया है व केवल पानी पी रहे हैं। खेती, जमीन, फसल व आने वाली नस्ल को बचाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। इसके मद्देनजर हरियाणा से किसानों ने फैसला लिया है कि उन्हीं खेतों के ट्यूबवेलों का पानी जगजीत सिंह

डल्लेवाल ग्रहण करें जिन्हें बचाने के लिए वह आमरण अनशन कर रहे हैं। इसी कड़ी के तहत हरियाणा से नारनौंद, राजपुरा, माजरी, डिडवादी, सोहटी, फग्गू, धर्मपुरा, खैराती खेड़ा, दादू, तिलोकेवाला, बीसला, करनोली, खुंबर, जंडवाला, आयलकी, छिनौली, मटिण्डू, गोपालपुर, नौल्था, माजरा, खुराना, रोजखेड़ा, जुल्हेड़ा, ढाणी छतरिया, ढाणी ठेबा, तमसपुरा, भरपूर, लक्कड़वाली, चमराडा, माढ़ा, मस्तगढ़, खरल, लोधर, फतेहपुरी, फुलां, अकांवली, सुंदरनगर हमजापुर सहित 50 से अधिक गांवों के खेतों के जल लेकर किसान मोर्चे पर पहुंचे। अब अगले दिनों छह, आठ, दस फरवरी को भी हरियाणा से किसान पानी लेकर खनौरी पहुंचेगे।

इसके साथ ही किसान काका सिंह कोटड़ा, जरनैल सिंह चाहल, गुरदास सिंह ने किसानों का खनौरी बॉर्डर पर पहुंचने का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जल नहीं है, बल्कि किसानों की भावना है जिन्हें यह महसूस होता है कि एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए चल रहे किसान आंदोलन में सहयोग करना जरूरी है।

रेशम विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को 17 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, ठगे 78 लाख रुपये

गोंडा (एजेंसी)

रेशम विभाग के उप निदेशक रामानंद मल्ल को डिजिटल अरेस्ट कर 78 लाख 80 हजार रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। 17 से अधिक दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रहने के बाद सोमवार को उप निदेशक ने पुलिस से शिकायत की। साइबर सेल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामानंद मल्ल ने शिकायती पत्र में कहा है कि 15 जनवरी को उनके मोबाइल फोन पर कॉल कर बताया गया कि उनके आधार कार्ड से 29 दिसंबर 2024 को दिल्ली से सिम प्राप्त किया गया है। उस फोन नंबर से अवैधानिक कार्य जैसे-पैसे मांगना, वीडियो बनाना, एमएमएस का कार्य हुआ है।

फोन करने वाले ने बताया कि द्वारिकापुरी पुलिस स्टेशन नई दिल्ली के हेडक्वार्टर से आपको कनेक्ट किया जा रहा है। पुलिस हेडक्वार्टर द्वारिकापुर के आईपीएस अधिकारी से बातचीत कराई गई, जिनके द्वारा बताया गया कि अशोक गुप्ता ने नई दिल्ली में एचडीएफसी बैंक में खाता खोला गया था। इस खाते में 68 करोड़ का मनी लॉन्डिंग, ड्रग स्मगलिंग और पैसे का लेन देन हुआ है।

नई दिल्ली आकर जमानत कराने की बात कही गई। इसके बाद प्रापर्टी, नौकरी व पैसे के लेनदेन के फ्लो की जांच के लिए अलग-अलग दिनों में 78 लाख 80 हजार रुपये लिया गया। बैंक से ऋण, मित्रों से उधार व जमीन बेचकर धनराशि जमा करनी पड़ी। दो लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही है। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। कहीं भी रुपये भेजने से पहले एक बार जांच कर लें। आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

मिल्कीपुर उपचुनाव : अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से की शिकायत, बोले- मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही पुलिस

लखनऊ (एजेंसी)

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में पुलिस मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल हैं।

ऐसे लोगों को तुरंत हटा कर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पुलिस अधिकारी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग तुरंत इस समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान ले कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं।

ये अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे

लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ज्ञात हो कि मिल्कीपुर उपचुनाव का मतदान सुबह सात बजे से शुरू है। तभी से

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में पुलिस मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल हैं

लगातार सपा द्वारा चुनाव आयोग को वीडियो सहित कई शिकायतें सपा की तरफ से की जा चुकी हैं। शिकायत के अनुसार, मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 103 पर भाजपा नेताओं द्वारा फर्जी मतदान कराए जाने की सूचना है। मिल्कीपुर विधानसभा के बूथ संख्या 6, 7 एवं 8, मोहम्मदपुर पर भाजपा के सैकड़ों नेता व कार्यकर्ता झंडा लिए मतदाताओं पर दबाव बना रहे हैं। विधानसभा में बूथ संख्या 120 पर भाजपा नेताओं द्वारा फर्जी मतदान कराए जाने की सूचना है। मिल्कीपुर विधानसभा के बूथ संख्या 193 पर पीठासीन अधिकारी और भाजपा के बूथ एजेंट स्वयं ही मतदाताओं का वोट डाल दे रहे हैं।

मिल्कीपुर में दो दर्जन से ज्यादा बूथों पर मिली शिकायतें : अवधेश प्रसाद

अयोध्या (एजेंसी)

उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटर्स अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि, अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि कई बूथों पर उन्हें शिकायतें मिली हैं। सपा सांसद ने कहा, दो दर्जन से ज्यादा बूथों पर एजेंटों को भगाए जाने, फर्जी वोटिंग और मशीनें बंद किए जाने की शिकायतें मिली हैं।

मैंने स्थानीय पर्यवेक्षकों और अपने नेताओं को इन मुद्दों की जानकारी दी है। ये घटनाएं अभी भी जारी हैं और कई शिकायतें मिल रही हैं। जैसे-जैसे शिकायतें मिलेंगी, पर्यवेक्षकों को जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने कहा, मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वोट डाला जा रहा है। भाजपा ऐसी स्थिति में है कि वह अपने प्रत्याशी की जमानत भी नहीं बचा पाएगी। इसी डर और असुरक्षा के कारण उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 9 से 10 बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है। पिछले तीन महीने से 16 मंत्री और 46 विधायक होने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा है। मिल्कीपुर का चुनाव यहां की जनता लड़ रही है। बता दें कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, चुनाव आयोग तुरंत इस समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान ले कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने वोट करने की अपील की। केशव प्रसाद मौर्य ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपील करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि पहले मतदान, फिर जलपान।

SYBLY INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off : Pawan Puri Muradnagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India, 201206
Email ID : syblyindustries1988@gmail.com, Contact No. : + 91-9953076480
CIN : L17111UP1988PLC009594

Unaudited Financial Result for the Quarter and Nine Months Year Ended on 31.12.2024

(₹ IN LACS EXCEPT EPS)

S.NO.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended	Year Ended
		CURRENT QUARTER	CORRESPONDING QUARTER	CURRENT NINE MONTHS	YEAR TO DATE FIGURES FOR PREVIOUS YEAR
		01.10.2024 to 31.12.2024 (`)	01.10.2023 to 31.12.2023 (₹)	01.04.2024 to 31.12.2024 (`)	01.04.2023 to 31.03.2024 (₹)
		Unaudited	unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operation	2,245.028	-	2,607.163	3.41
2	Net Profit / Loss for the period before tax and exception items	1,054.091	-9.66	1,401.424	(101.39)
3	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exception itmes)	1,054.091	3.59	1,401.424	(473.08)
4	Net Profit/ Loss for the period after tax (after exception itmes)	1,054.091	3.59	1,401.424	(352.24)
5	Total [Comprehensive income/ loss for the period [comprising profit/ loss for the period (after tax) and other comprehensive income/ loss (after tax)]	1,054.091	3.59	1,401.424	(352.24)
6	Paid up equity share capital	915.665	915.66	915.665	915.67
7	other equity	-	(486.36)	-	(830.35)
8	Earning per share (of Rs. 10/- each) after exception item Basic & Diluted	11.512	0.04	15.305	(3.85)

Note

1. The above unaudited standalone financial results for the quarter and nine months ended on December31, 2024 were reviewed by the Audit Committee at the meeting and approved by the Board of Directors and taken on record at the meeting held on February 05th, 2025
2. The above is an extract of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available in the Company's website (www.).

Date : 05.02.2025
Place : New Delhi

For and on behalf of board of directors of
SYBLY INDUSTRIES LIMITED
CHIRAG
(Managing Director)
DIN : 10728185

Tulsi Gabbard gets Intelligence Committee's vote to be Director of National Intelligence

AMERICA (AGENCY)

Hindu-American Tulsi Gabbard, US President Donald Trump's controversial pick to oversee spy agencies, has been approved by a key Senate committee for Director of National Intelligence (DNI) in a private vote, paving the way toward a wider Senate vote on her confirmation. The Republican-led Senate Select Committee on Intelligence approved Gabbard's nomination in a closed committee vote of 9-8, along party lines. The full Senate is expected to vote on her confirmation as early as next week, the Washington Post reported. Gabbard, 43, a former Democratic congresswoman from Hawaii, had faced bipartisan scepticism about her suitability for overseeing the spy agencies. "The Intelligence Committee just voted for Tulsi Gabbard's nomination to be the Director of National Intelligence to the full United States Senate," Senate Intelligence Committee Chair Tom Cotton told reporters on Tuesday after the closed-door vote. "We look forward to her confirmation and working with her to keep America safe," he was quoted as saying by the Hill. The vote took place only hours after Senator Todd Young, a key Republican swing vote, announced that he would support her. Gabbard had secured another big win on Monday as Sen. Susan Collins (R-Maine) said that she would back her in the committee vote. A four-term Congresswoman, 2020 presidential candidate and NYT bestselling author, Gabbard, 43, is a veteran with three deployments to war zones in the Middle East and Africa. She recently moved from being a Democrat to a Republican member. In October 2022, she announced she was leaving the Democrat Party, and becoming an Independent. On August 26, 2024, Gabbard formally endorsed Trump for a second term and soon after began serving as co-chair of his transition team. On October 22, 2024, she joined the Republican Party because of President-elect Trump's leadership and how he has been able to transform the Republican Party, bringing it back to the party of the people and the party of peace. From the moment Trump announced Gabbard as his nominee to be DNI, questions have cropped up about her past views and statements. Those include her 2017 meeting with then-Syrian President Bashir al-Assad, which occurred as he was accused of using chemical weapons on his own people, as well as her stance on Russia given multiple comments she made about the war with Ukraine that were considered sympathetic to Moscow and were echoed on Russian state.

TV. As per the US law, all the Cabinet ranking positions and several other senior administration positions need to be confirmed by the US Senate. It starts with a confirmation hearing by their respective Senatorial committees.

US Postal Service suspends inbound parcels from China, Hong Kong after Trump shuts trade loophole

HONG KONG (AGENCY)

The U.S. Postal Service said it would temporarily suspend parcels from China and Hong Kong, after President Donald Trump shut a trade loophole this week used by retailers including Temu and Shein to ship low-value packages duty-free to the U.S. The Trump administration imposed an additional 10% tariff on Chinese goods that came into effect on Tuesday and moved to close the "de minimis" loophole that allows importers and U.S. shoppers to avoid paying tariffs for packages worth less than $800. USPS said the change will not impact the flow of letters and 'flats' from China and Hong Kong. It did not immediately comment on whether this was tied to Trump's change to ending de minimis shipments from China and other countries. Fast-fashion retailer Shein and online dollar-store Temu, both of which sell products ranging from toys to smartphones, have grown rapidly in the U.S. thanks in part to the de minimis exemption. The two firms together likely accounted for more than 30% of all packages shipped to the United States each day under the de minimis provision, the U.S. con-

gressional committee on China said in a June 2023 report. Nearly half of all packages shipped under de minimis come from China, according to the report. Shein and Temu did not immediately reply to a request for comment. "In our view, the USPS would require some time. to sort out how to execute the new taxes before allowing Chinese packages to arrive in the U.S. again," said Chelsey Tam, senior equity analyst, Morningstar. "This is a significant challenge for them because there were 4 million de minimis package per day in 2024, and it is difficult to check all the packages - so it will take time." Trump's crackdown on de minimis would make the products sold by the likes of Shein and Temu more expensive but is unlikely to dramatically impact shipment volumes, experts said. "E-commerce volumes out of China grew 20-30% last year, so it's going to take a sledgehammer to crack that level of consumer demand and I'm not sure de minimis alone is enough," said Niall van de Wouw, Chief Airfreight Officer at freight platform Xeneta. "They will still be cheaper than buying through retailers in the U.S. Delays in receiving the goods due to operational disruptions.

Trump says US will 'take over' Gaza Strip, 'own it' and undertake economic development

GAZA (AGENCY)

In a surprising announcement, President Donald Trump said the US "will take over the Gaza Strip", "own it" and undertake economic development there that will create "unlimited numbers of jobs and housing". Trump made these remarks on Tuesday during a joint press conference in the White House with visit-

ing Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu standing beside him. Trump also suggested that the US develop the land but gave no details on who would be allowed to live there. "The US will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site, and get rid of the destroyed buildings," Trump said. "Create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area, do a real job, do something different," he said. "The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. They instead can occupy all of a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony, instead of having to go back and do it again," Trump said. Asked about the possibility of sending US troops to Gaza, Trump said the US would "do what is necessary" as he laid out plans for the US to take the area over, and suggested he would visit the territory. Calling the Gaza Strip a "symbol of death and destruction" and a "hell hole right now", Trump said it is "so bad for the people anywhere near it, and especially those who live there... It's been very unlucky. It's been an unlucky place for a long time." Trump added that "we'll be a great keeper of something that is very, very strong, very powerful and very, very good for the area, not just for Israel, for the entire Middle East, very important. And we'll again have thousands of jobs.

Why Donald Trump's proposal on Gaza is ringing alarm bells in the region

WASHINGTON (AGENCY)

President Donald Trump's plan for the United States to take over the war-ravaged Gaza Strip and develop it economically touches on one the most sensitive issues in the Arab-Israeli conflict. Trump's plans are likely to heighten fears among Palestinians in Gaza, which had a pre-war population of around 2.3 million, of being driven out of the coastal strip, and stoke concern in Arab states that have long worried about the destabilising impact of any such exodus.

Palestinians have long been haunted by what they call the "Nakba", or catastrophe, when 700,000 of them were dispossessed from their homes during the war that surrounded the creation of Israel in 1948. Many were driven out or fled to neighbouring Arab states, including to Jordan, Syria and Lebanon, where many of them and their descendants still live in refugee camps. Some went to Gaza. Israel disputes the account that they were forced out.

The latest conflict, currently paused amid a fragile ceasefire agreement, has seen an unprecedented Israeli bombardment and land offensive in Gaza, devastating urban areas. Most Gazans have been displaced

several times during Israel's offensive, launched after the Oct. 7, 2023 attack on Israel by the Palestinian militant group Hamas that killed 1,200 people, according to Israeli tallies. More than 47,000 people have been killed in Gaza since then, according to Palestinian health officials. Hamas official Sami Abu Zuhri said on Wednesday Trump's remarks about taking over Gaza are 'ridiculous' and 'absurd' and could ignite the region.

How have Palestinians moved during this conflict? Before Israel launched its offensive in 2023, it told Palestinians in north Gaza to move to what it said were safe areas in the south. As the offensive expanded, Israel told them to head further south towards Rafah, on the border with Egypt.

Later in the war, before launching a campaign in Rafah, it instructed them to move to a new designated humanitarian zone in Al-Mawasi, an area that stretches 12 km (7 miles) along the coast, starting from the western areas of Deir Al-Balah in central Gaza to Khan Younis and Rafah in the south. According to U.N. estimates, up to 85% of the population of Gaza - one of the world's most densely populated areas - have already been displaced from their homes. Could a major displacement from Gaza happen? Many Palestinians in Gaza have said they would not leave the enclave even if they could because they fear it might lead to another permanent displacement in a repeat of 1948.

Egypt and other Arab nations strongly oppose any attempt to push Palestinians over the border. Like Palestinians, they fear any mass movement across the border would further undermine prospects for a "two-state solution" - the idea of creating a state of Palestine next to Israel - and leave Arab nations dealing with the consequences.

Saudi Arabia said it would not establish ties with Israel without the creation of a Palestinian state, contradicting Trump's claim that Riyadh was not demanding a Palestinian homeland. The United States had led months of diplomacy to get Saudi Arabia, one of the most powerful and influential Arab states, to normalise ties with Israel and recognise the country. But the Gaza war led Riyadh to shelve the matter in the face of Arab anger over Israel's offensive.

From the earliest days of the conflict, Arab governments, particularly Egypt and Jordan, have said Palestinians must not be driven from land where they want to make a future state, which would include the occupied West Bank and Gaza. What have Israel's government and its politicians said? Israel's then-Foreign Minister Israel Katz, now serving as defence minister, said on Feb. 16, 2024, that Israel had no plans to deport Palestinians.

Briefs News

Trump withdraws US from UN Human Rights Council, stops funding for Palestinian refugees

ISRAELI (AGENCY) President Donald Trump announced Tuesday that the United States will withdraw from the top U.N. human rights body and will not resume funding for the U.N. agency helping Palestinian refugees. The US left the Geneva-based Human Rights Council last year, and it stopped funding the agency assisting Palestinian refugees, known as UNRWA, after Israel accused it of harboring Hamas militants who participated in the surprise October 7, 2023, attacks in southern Israel, which UNRWA denies. Trump's announcement came on the day he met with visiting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, whose country has long accused both the rights body and UNRWA of bias against Israel and antisemitism. Trump's executive orders also call for a review of American involvement in the Paris-based U.N. Educational, Scientific and Cultural Organization, known as UNESCO, and a review of US funding for the United Nations in light of "the wild disparities in levels of funding among different countries." The United States, with the world's largest economy, pays 22 per cent of the U.N.'s regular operating budget, with China the second-largest contributor. "I've always felt that the U.N. has tremendous potential," Trump told reporters in the Oval Office. "It's not living up to that potential right now. ... They've got to get their act together."

China tariff strikeback: Beijing retaliates against Donald Trump's new trade measures

BEIJING (AGENCY) Beijing responded swiftly on Tuesday to the tariffs President Donald Trump had promised, announcing a fusillade of countermeasures targeting American companies and imports of critical products. Trump's 10 per cent tariff on all Chinese products went into effect at 12.01am on Tuesday, the result of an executive order issued over the weekend aimed at pressuring Beijing to crack down on fentanyl shipments into the US. The Chinese government came back with a series of retaliatory steps, including additional tariffs on liquefied natural gas, coal, farm machinery and other products from the US. It also said it had implemented restrictions.

Trump administration puts on leave USAID staff globally in dramatic aid overhaul

AMERICA (AGENCY)

The Trump administration on Tuesday announced that it was going to put on leave all directly hired employees of the U.S. Agency for International Development globally and recall thousands of personnel working overseas. "On Friday, February 7, 2025, at 11:59 pm (EST) all USAID direct hire personnel will be placed on administrative leave globally," said an announcement on the USAID web site, which has been down since the weekend. Some personnel "responsible for mission-critical functions, core leadership and specially designated programs" were excepted from the move, it said. USAID's workforce totals more than 10,000, with about two-thirds of that staff serving overseas, according to the Congressional Research Service (CRS). The agency has more than 60 country and regional missions. For USAID staff overseas, Washington was preparing a plan in coordination with the State Department and

would pay for the return travel of personnel to the United States within 30 days, the announcement said. It added that the USAID leadership was going to consider case-by-case exceptions based on personal hardship or concerns over mobility and safety. "Thank you for your service," the announcement finished. The shocking overhaul, which risks upending the lives of thousands of staff and their families, comes as President Donald Trump moves merge USAID, Washington's that distributes billions of dollars worth of aid abroad, with the State Department and effectively dismantle the agency as an independent entity. On Monday, Secretary of State Marco Rubio told reporters he was now the acting head of USAID, calling the agency "completely unresponsive" and accusing staff there of being "unwilling to answer simple questions" about programs. He informed Congress in a letter of the looming reorganization of the agency, saying some parts of USAID might be absorbed by the State Department and the remainder may be abolished. But because Congress established USAID as an independent establishment within the executive branch, the President does not have the authority to abolish it without congressional authorization, according to a CRS report this week. Hundreds of USAID programs covering lifesaving aid across the globe came to a halt after Trump on Jan. 20 ordered a freeze of most U.S. foreign aid, saying he wanted to ensure it is aligned with his "America First" policy. He tasked billionaire Elon Musk, who has falsely accused USAID of being a "criminal" organization, with scaling down the agency. The announcement on the USAID website went online hours after State Department officials were told by Peter Marocco, a Trump appointee who was on Monday tasked with overseeing the agency's operations, that all USAID staff and their families should be recalled, sources said. Tuesday night's announcement caps nearly two weeks of mayhem at the agency, where dozens of staff at the headquarters in DC were put on leave and hundreds of internal contractors were laid off. Implementing partners of USAID. are facing financial trouble on the back of stop-work orders from the State Department. Waivers have been issued for some emergency life-saving assistance. In fiscal year 2023, the United States disbursed $72 billion of aid worldwide on everything from women's health in conflict zones to access to clean water, HIV/AIDS treatments, energy security and anti-corruption work. It provided 42% of all humanitarian aid tracked by the United Nations in 2024. The funding, less than 1% of the United States' total budget, is instrumental.

SYBLY INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off : Pawan Puri Muradnagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India, 201206
Email ID : syblyindustries1988@gmail.com, Contact No. : + 91-9953076480
CIN : L17111UP1988PLC009594

Unaudited Financial Result for the Quarter and Nine Months Year Ended on 31.12.2024

(₹ IN LACS EXCEPT EPS)

S.NO.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended	Year Ended
		CURRENT QUARTER	CORRESPONDING QUARTER	CURRENT NINE MONTHS	YEAR TO DATE FIGURES FOR PREVIOUS YEAR
		01.10.2024 to 31.12.2024 (`)	01.10.2023 to 31.12.2023 (₹)	01.04.2024 to 31.12.2024 (`)	01.04.2023 to 31.03.2024 (₹)
		Unaudited	unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operation	2,245.028	-	2,607.163	3.41
2	Net Profit / Loss for the period before tax and exception items	1,054.091	-9.66	1,401.424	(101.39)
3	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exception itmes)	1,054.091	3.59	1,401.424	(473.08)
4	Net Profit/ Loss for the period after tax (after exception itmes)	1,054.091	3.59	1,401.424	(352.24)
5	Total [Comprehensive income/ loss for the period [comprising profit/ loss for the period (after tax) and other comprehensive income/ loss (after tax)]	1,054.091	3.59	1,401.424	(352.24)
6	Paid up equity share capital	915.665	915.66	915.665	915.67
7	other equity	-	(486.36)	-	(830.35)
8	Earning per share (of Rs. 10/- each) after exception item Basic & Diluted	11.512	0.04	15.305	(3.85)

Note

1. The above unaudited standalone financial results for the quarter and nine months ended on December31, 2024 were reviewed by the Audit Committee at the meeting and approved by the Board of Directors and taken on record at the meeting held on February 05th, 2025
2. The above is an extract of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available in the Company's website (www.).

Date : 05.02.2025
Place : New Delhi

For and on behalf of board of directors of
SYBLY INDUSTRIES LIMITED
CHIRAG
(Managing Director)
DIN : 10728185